विदेशी संस्थागत निवेशक व वेन्चर कैपिटल कम्पनियों ने सरकार से किया संवाद

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग– *"हम व्यावसायिक गतिरोधों को दूर कर प्रदेश की छवि एवं वास्तविकता के अन्तर को कम करने हेतु प्रयासरत हैं।"*

"उत्तर प्रदेश के अनछुये ग्रामीण बाजारों में छुपी है सफलता की कुंजी"

"औद्योगिक सेवा गारन्टी अधिनियम का ड्राफ्ट अंतिम चरण में"

लखनऊ, 21 नवम्बर, 2013:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा निवेशोन्मुख वातावरण बनाने के गम्भीर प्रयासों के फलस्वरूप निवेशकों से आशातीत रुचि प्राप्त हो रही है। **कई विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors-FIIs) तथा उद्यम पूंजी उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों के उच्चाधिकारियों के 20 सदस्यीय दल ने प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए आज यहाँ प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी)–डॉ. सूर्य प्रताप सिंह एवं प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, मनोज सिंह से भेंट कर गहन वार्ता की।**

ऐम्बिट कैपिटल की अगुवाई में आए इस दल ने उत्तर प्रदेश में निवेश के माहौल तथा चुनौतियों और उन चुनौतियों से निपटने की रूपरेखा के विषय में जानना चाहा।

अतिथियों का स्वागत करते हुए **प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी)–डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने कहा**– *"20 करोड़ निवासियों के इस राज्य में विशाल उपभोक्ता आधार के कारण प्रगति और विकास को रोका नहीं जा सकता। पश्चिम में सफल होने वाला कोई भी बिज़नेस मॉडल यहाँ भी सफल होगा, गत् पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के उन कुछ राज्यों में से एक रहा है जहाँ 7 प्रतिशत् की दर से तरक्की हुई है।"* **उन्होंने कहा कि उ.प्र. का बढ़ता हुआ उपभोक्ता वर्ग देश का 14 प्रतिशत् है, जो विशालतम है।"**

राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण होने को रेखांकित करते हुए **प्रमुख सचिव ने कहा**– *"उत्तर प्रदेश के अनछुये ग्रामीण बाजारों में छुपी है सफलता की कुंजी।"* **उन्होंने कहा** कि प्रचुर संसाधनों एवं कच्चे माल के प्रसंस्करण व मूल्य–संवर्धन में असीम सम्भावनाएं है, सरकार व्यावसायिक गतिरोधों को दूर कर प्रदेश की छवि एवं वास्तविकता के अन्तर को कम करने हेतु प्रयासरत हैं, जिससे यहाँ निवेश आ सके।

डॉ सूर्य प्रताप सिंह ने कहा– *"राज्य सरकार एक औद्योगिक सेवा गारन्टी अधिनियम लाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। इससे न केवल उद्यमियों को समय से स्वीकृतियाँ मिल सकेंगी अपितु जो अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे उनके दण्ड का प्राविधान भी होगा।"*

इससे पहले वार्ता की शुरुआत करते हुए **ऐम्बिट कैपिटल के सीईओ–संस्थागत् इक्विटी, सौरभ मुखर्जी** ने उत्तर प्रदेश द्वारा गत् पाँच वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति करने के कारणों, राज्य में निवेश–वातावरण को सुधारने तथा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के विषय में जानना चाहा।

उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए **पीटीसी इण्डस्ट्रीज़ के प्रबन्ध निदेशक, सचिन अग्रवाल ने कहा** कि प्रचलित छवि के विपरीत उनकी लखनऊ स्थित इकाई में कई वर्षों से एक भी कार्य–दिवस का नुकसान नहीं हुआ। इतना ही नहीं श्रमिकों को नौकरी से निकाले जाने की दर भी उत्तर प्रदेश में द्वितीय न्यूनतम है। **उन्होंने कहा**– "नई राज्य सरकार के उद्योगों के प्रति सकारात्मक रुख का हम स्वागत करते हैं, यह समय राज्य में निवेश करने के लिए उत्तम है।"

टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस) के प्रमुख परामर्शी, जयंत कृष्णा ने कहा कि कम्पनी का प्रदेश में अच्छा अनुभव रहा है। हमारी लखनऊ इकाई की उत्पादकता टीसीएस के अन्यत्र उत्कृष्ट केन्द्रों के बराबर रहती है। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि टाटा मोटर्स की लखनऊ इकाई कम्पनी की दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी इकाई है।

प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से *कैपिटल ग्लोबल* के मैक्रो एनालिस्ट एण्ड स्ट्रैटिजिस्ट– जीतू पंजाबी; ***एसबीआई एमएफ*** के फण्ड मैनेजर–अजीत डांगे; ***फ्रैंकेलिन टेम्पलटन*** के फण्ड मैनेजर–आनन्द वासुदेवन; ***प्रेमजी इन्वेस्ट*** के सीनियर फण्ड मैनेजर–शशि बालाचन्दर; ***इण्डिया वैल्यू फण्ड*** के निदेशक–अमित हिरावत; ***मॉर्गन स्टेनले इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट*** के फण्ड मैनेजर स्वानन्द केलकर; ***इण्डिया कैपिटल*** के वाइस प्रेज़िडेंट मिहिर शाह, हितेश जैन, श्रीराम वास्मानी; ***इन्वेस्को*** के निदेशक शेखर सम्भशिवन; ***यूनियन बैंकेयर प्राइवी*** के फण्ड मैनेजर गणेश चिदम्बरम तथा ***मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस, सुन्दरम म्यूचल फण्ड*** व ***ऐम्बिट कैपिटल*** के उच्चाधिकारी शामिल थे।